



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 2007/श्रावण 16, 1929

No. 223]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 2007/SRAVANA 16, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2007

विषय : अमरीका, थाईलैंड तथा रूस से पोटेशियम कार्बोनेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/6/2007-डीजीएडी.— | जबकि मै0 गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड वदोदरा ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् पाटनरोधी नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें अमरीका, थाईलैंड एवं रूस (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम कार्बोनेट (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और इसरि : संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पाटनरोधी जांच करने एवं इस प्रकार के पाटित संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

और जबकि प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग की क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं और वे एतद्वारा किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं।

2. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद पोटेशियम कार्बोनेट है। पोटेशियम कार्बोनेट सफेद प्रस्वेद्य अकार्बनिक यौगिक होता है तो पाउडर या दानेदार रूप में उपलब्ध है। इसे पोटाश, पर्लेश, पोटाश के

कार्बोनेट डिपोटेजियम लवण और टारटर लवण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह बताया गया है कि पोटेसियम कार्बोनेट जल में विलेय है परंतु अल्कोहल में अविलय है। जैसा कि बताया गया है कि इसका उत्पादन पोटेसियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। विचाराधीन उत्पाद को प्रस्वेद्य (जो प्रायः नभीयुक्त या गीला होता है) ठोस पदार्थ बताया गया है जिसका प्रयोग साबुन एवं कांच के उत्पादन में किया जाता है।

ऐसा बताया जाता है कि पोटाशियम कार्बोनेट के उत्पादन हेतु प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में कास्टिक पोटाश की जरूरत होती है और कास्टिक पोटाश के उत्पादन हेतु प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में पोटाशियम क्लोराइड (केसीएल) की जरूरत होती है। विनिर्माण प्रक्रिया को पोटाशियम क्लोराइड → पोटाशियम हाइड्रोक्साइड → पोटाशियम कार्बोनेट के रूप में बताया जाता है। पोटाशियम कार्बोनेट "अकार्बनिक रसायन" (कीमती धातुओं का कार्बनिक अथवा अकार्बनिक मिश्रण) की श्रेणी के अंतर्गत आता है और यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। 8 अंकीय स्तर पर विचाराधीन उत्पाद अर्थात् पोटाशियम कार्बोनेट आईटीसी (एचएस) कोड 28364000 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

पोटाशियम कार्बोनेट का प्रयोग मुख्यतः टीवी पिकचर ट्यूबों, लैम्प एवं ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक शीशे के विनिर्माण उर्वरक उद्योग, रबड़ उद्योग, कीटनाशी उद्योग, औषध एवं भेषज रंजक एवं पोटाशियम आधारित रसायन उद्योग में किया जाता है।

3. घरेलू उद्योग एवं इसकी स्थिति

याचिकाकर्ता, गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स लि० के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य उत्पादक अर्थात् मै० स्टैंडर्ड अल्काली (स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लि० की एक इकाई) और मै० श्री रेयलासीमा अल्कालीज हैं। ऐसा बताया जाता है कि मै० श्री रेयलासीमा अल्कालीज ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु क्षमता का सृजन कर लिया है और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। तथापि, ऐसा बताया जाता है कि मै० स्टैंडर्ड अल्काली ने श्रमिकों के असंतोष के कारण फरवरी, 2006 से उत्पादन बंद कर दिया है। याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादन किया जाने वाला उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। याचिका नियमों के अंतर्गत स्थिति संबंधी शर्तों को पूरा करती है और याचिकाकर्ता नियमों के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) (क) के अनुसार याचिकाकर्ता के पास घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जांच हेतु वर्तमान याचिका दाखिल करने का आधार है।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयात वस्तुओं से भौतिक एवं रासायनिक गुणों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वस्तुओं की कीमत, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के लिहाज से तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और दोनों एक दूसरे से काफी मिलती हैं। यह भी दावा किया गया है कि उपभोक्ताओं ने दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को पाटनरोधी नियमों के अर्थ भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

5. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश यूएसए, थाईलैण्ड तथा रूस हैं, जिन्हें इस जांच के प्रयोजनार्थ एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है।

6. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ताओं ने यूएसए के लिए उस देश में पोटैशियम कार्बोनेट की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। जहां तक थाईलैण्ड का प्रश्न है, याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों के अनुसार कच्चे माल की कीमत तथा घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत, जिसमें लाभ की समुचित गुंजाइश का भी समायोजन किया गया है, पर विचार करते हुए उत्पादन की संरचित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना द्वार स्तर पर किया गया है। रूस के मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि रूस एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, अतः उसने नियमावली के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का दावा किया है, और इस प्रयोजनार्थ यूएसए को सहोदर देश मानने का सुझाव दिया है।

7. निर्यात कीमत

निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा दिसम्बर, 2006 तक संकलित सौदेवार आंकड़ों तथा आईबीआईएस द्वारा उसके बाद की अवधि हेतु संकलित सौदेवार आंकड़ों के आधार पर किया गया है। सीआईएफ कीमत तथा कारखाना- द्वार निर्यात कीमत की गणना हेतु माल भाड़े, ऋण लागत, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय मालभाड़े, बीमा तथा कमीशन आदि की दृष्टि से कीमत समायोजन के विभिन्न तत्वों को अपनाते हुए निवल निर्यात कीमत का भी निर्धारण किया गया है।

8. पाटन मार्जिन

इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप पाटित आयातों में समग्र रूप से वृद्धि और भारत में उत्पादन एवं खपत में सापेक्ष वृद्धि, अत्यधिक कीमत कटौती, यूएसए, थाईलैण्ड तथा रूस के बाजार हिस्से में बढ़ोत्तरी और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी, लाभों, लगाई गई पूंजी से आय, नकद लाभ आदि में आयी गिरावट के बारे में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण याचिकाकर्ताओं को हो रही वास्तविक क्षति का पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है। इसके अलावा, वास्तविक क्षति के अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि आयातों में वृद्धि की दर, अत्यधिक कीमत कटौती और पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताओं के आधार पर पाटित आयातों से वास्तविक क्षति का खतरा उत्पन्न हो रहा है।

10. जांच अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2006 से मार्च, 2007 तक है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2003- मार्च, 2004; अप्रैल, 2004- मार्च, 2005; अप्रैल, 2005- मार्च, 2006 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होंगी।

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध ज्ञात निर्यातकों और भारत में स्थित उनके दूतवासों के जरिए उसकी सरकार, भारत में संबंधित के रूप में ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग के अलग- अलग सूचना दी गई है ताकि वे विनिर्दिष्ट ढंग एवं विधि से सभी संगत सूचनाएं दाखिल कर सकें। वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार निम्न पते पर लिख सकता है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा सं. 240, उद्योग भवन,

नई दिल्ली- 110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है।

12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें उक्त सूचना, उन्हें लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज करेंगे।

13. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की राय में सूचना का संक्षिप्तिकरण संभव नहीं है, तो उसके कारणों का विवरण प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से मना करता है, अथवा उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को उचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2007

Subject : Initiation of Anti-Dumping investigation concerning the imports of Potassium Carbonate from USA, Thailand and Russia.

No. 14/6/2007-DGAD.— Whereas M/s. Gujrat Alkalies & Chemicals Limited, Vadodra have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), alleging dumping of Potassium Carbonate (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from USA, Thailand and Russia (hereinafter referred to as the subject countries) and have therefore requested for initiation of an anti-dumping investigation against the imports of the subject goods from the subject countries and levy anti-dumping duty on the such dumped subject goods.

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

2. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present petition is Potassium Carbonate.

Potassium Carbonate is white, deliquescent inorganic compound, available in powder and granular form. It is also stated to be known as Potash, Pearl Ash, Carbonate of Potash, Dipotassium Salt, and Salt of Tartar. Potassium Carbonate is further stated to be soluble in water and insoluble in alcohol. It is stated to be produced by electrolysis of potassium chloride. The product under consideration is stated to be a deliquescent (usually damp or wet) solid, used in the production of soap and glass.

Production of Potassium Carbonate is stated to require Caustic Potash as major raw material, and production of Caustic Potash is stated to require Potassium Chloride (KCL) as the major raw material. The process of manufacture is stated to be Potassium Chloride-->Potassium Hydroxide-->Potassium Carbonate. Potassium Carbonate falls under category of "Inorganic Chemicals" (Organic or Inorganic Compound of Precious Metals) and is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act. At 8 digit level the product under consideration i.e. Potassium Carbonate is classified under ITC (HS) code 28364000.

Potassium Carbonate is primarily used in manufacturing of TV Picture Tubes, GLS Lamp & Ophthalmic Glass, Fertilizer Industry, Rubber Industry, Pesticide industry, Drug & Pharmaceuticals, Dyes and Potassium based chemical industries.

3. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Apart from the petitioner Gujrat alkalies & Chemicals Limited, there are two other producers of the subject goods in India viz. M/s. Standard Alkali (A unit of Standard Industries Limited) and M/s. Sree Rayalseema Alkalies. M/s. Sree Rayalseema Alkalies are stated to have created capacity for production of subject goods and commenced commercial production. M/s. Standard Alkali is however stated to have suspended production since February 2006 due to labour unrest. The production by Petitioner Company constitutes a major proportion in the Indian production. The petition satisfies the condition of standing under the Rules and the petitioner constitutes "**Domestic Industry**" within the meaning of the Rules. The applicant has the standing to file the present petition for anti-dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3) (a) of Anti-Dumping Rules.

4. LIKE ARTICLE

Petitioner has claimed that there is no significant difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to ones imported from subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both are technically and commercially substitutable and hold closely resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. For the purpose of present investigation, product under consideration produced by the petitioner is being treated as like article to one imported from the subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

5. COUNTRIES INVOLVED

The countries involved in the present investigations are USA, Thailand and Russia here in after referred to as subject countries for the purposes of this investigation.

6. NORMAL VALUE

The petitioners have claimed normal value for USA on the basis of price of Potassium Carbonate in that country. With regard to Thailand, petitioner has claimed normal value on the basis of constructed cost of production considering raw material price as per DGCI&S data and conversion cost of the domestic industry, duly adjusted to reflect reasonable profit margin. Normal value determined is at ex-factory level. In case of Russia, petitioner has claimed that Russia is a non market economy and therefore claimed determination of normal value in accordance with Para 7 of the Rules., suggesting USA as surrogate country for this purpose.

7. EXPORT PRICE

The export price has been determined based on the transaction wise data compiled by DGCI&S up to December 2006 and transaction wise data compiled by IBIS for subsequent period. Net export price has also been determined from the CIF price and adopting various elements of price adjustments towards freight, credit cost, bank charges, inland freight, insurance and commission etc to arrive at ex-works export price.

8. DUMPING MARGIN

There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net export price indicating, prima-facie, that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

9. INJURY AND CAUSAL LINK

Petitioners have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping in terms of increase in imports in absolute terms and relative to production & consumption in India, significant price undercutting, increase in market share of USA, Thailand and Russia, decline in the market share of the domestic industry, deterioration in profits, return on capital employed and cash profit etc. There is sufficient, prima-facie evidence of material injury being suffered by the petitioners, caused by dumped imports from subject countries. Further, in addition to material injury, petitioners have claimed that the imports are causing threat of material injury from the dumped imports based on rate of increase in imports, significant price undercutting and significant unutilized capacities.

10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI):

The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is April 2006-March 2007. The injury investigation period will however, cover the period April, 2003-March, 04; April, 2004-March, 05; April, 2005-March, 06 and period of investigation.

11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject countries and their Government through their embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

13. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

14. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6 (7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority